दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 250, बुधवार, 16 अक्टुबर, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कैप्टन का बड़ा बयान, करतारपुर साहिब अब एक कॉरीडोर है न कि पाकिस्तान

लुधियाना। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पाकिस्तान नहीं जाएंगे। यह ऐलान आज उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान हमारे जवानों पर गोलीबारी बंद नहीं करेगा और आतंकवादी गतिविधयां बढ़ाव नहीं देगा, तब तक वह पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कैप्टन ने यह भी स्पष्ट किया कि वह पहले जत्थे के साथ अगर करतारपुर साहिब जाते हैं तो इसे यह न समझा जाए कि वह पाकिस्तान गए हैं। उन्होंने कहा कि करतारपुर साहिब अब एक कॉरिडोर है पाकिस्तान नहीं। कैप्टन अमरिन्दर सिंह उपचुनाव के प्रचार के लिए मंगलवार को लुधियाना के मुलांपुर दाखा पहुंचे थे। उन्होंने ने कहा कि करतापुर साहिब के खुले दर्शन दीदार होने चाहिए। 1927 में मेरे दादा जी ने गुरुद्वारा साहिब की सेवा करवाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी अकाली दल की स्टेज पर जाएंगे या नहीं, यह अभी तक पीएम आफिस की तरफ से लिखित रूप में सामने नहीं आया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अकाली दल राजनीति खेल रहा है। सुखबीर बादल और हरसिमरत बादल बेकार की बातें कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि यह पहले ही स्पष्ट र दिया गया है कि गुरुद्वारा साहिब के अंदरूनी कामों का प्रबंध एसजीपीसी करे और बाहर के काम सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि 550वें प्रकाश पर्व को लेकर समागमों का काम श्री अकाल तख्त साहिब के अनुसार ही होगा। हालांकि 12 नवंबर को गुरू नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर स्टेज का मामला फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म के अनुसार ही जा रहे हैं।

आतंकी हमले के बाद घाटी में एक बार फिर बंद हुई एसएमएस सेवा

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा शुरु होने के कुछ ही घंटों बाद एसएमएस सेवा को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे एसएमएस सेवा बंद कर दी गई। खबर है कि सोमवार को शोपियां जिला में हुई आतंकी घटना के बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल, सोमवार रात 8 बजे शोपियां जिले में दो आतंकवादियों ने राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी और एक बगीचे के मालिक पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम शरीफ खान है। हमलावर आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। आतंकवादियों का यह हताशा शीरमल गांव में किया गया क्योंकि घाटी में फलों के परिवहन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि 25 लाख से अधिक प्रीपेड मोबाइल फोन और व्हाट्सएप्प समेत अन्य इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बाधित रहेंगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कहा था कि इंटरनेट सेवाएं जल्दी ही बहाल की जाएंगी लेकिन सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इसमें दो महीने का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड सेवाओं पर फैसला अगले महीने लिया जा सकता है। कश्मीर में 5 अगस्त को मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जब केंद्र सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। जम्मू में प्रतिबंध के कुछ दिनों बाद ही संचार सेवाएं बहाल कर दी गई थी और अगस्त मध्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी शुरू कर दी गई थीं। 18 अगस्त को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई।

जम्मू-कश्मीर : गांदरबल से हिजबुल के दो आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले से पाकिस्तान समर्थक संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से जुड़े दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि एक विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दो आतंकवादी को गिरफ्तार किया। उनकी शिनाख्त चांदी खटाना और वाजिद अली खटाना के तौर पर हुई है। दोनों जंडीवाड़ा राजौरी के रहने वाले हैं। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये दोनों आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा हैं और सक्रिय आतंकवादियों के लिए मददगार के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे आतंकवादियों को हथियारों और गोला-बारूद देने और इलाके में आतंकी हमला करने के लिए सक्रिय दहशतगर्दों का मार्गदर्शन करने के लिए भी जिम्मेदार थे। इसके अलावा उनका आतंकवाद के नेटवर्क को मजबूत करना भी काम था। प्रवक्ता ने बताया कि उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री और हथियार तथा गोला-बारूद बरामद हुआ है। आपत्तिजनक सामग्री को जब्त कर लिया गया है।

दिल्लीवालों पर भारी पड़ेगी इस बार की दिवाली...दमघोंटू हवा चलने की आशंका

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषित हवा की स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है और पराली जलाने का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। प्रदूषण के कारणों में पराली का योगदान आठ प्रतिशत रहा। सबसे ज्यादा प्रभाव वाहनों, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले तत्वों से दिख रहा है। हवा की चाल बदलने से धुंध कुछ कम जरूर दिखाई दी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में हवा का दबाव ऐसा बन रहा है जिससे हालात सुधरेंगे। लेकिन अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से प्रदूषण फिर बढ़ना तय है। सफर के मुताबिक हवा की दिशा अभी तक दक्षिण-पश्चिम की तरफ है यानी पंजाब और हरियाणा की तरफ से आने वाली हवाओं में पराली जलाने का धुआं भी आ रहा है। साथ ही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मुसीबत में इजाफा करेगा। सफर के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जहां सर्दी बढ़ेगी, वहीं प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान हवाएं भी कम गति पर चलेंगी जिससे प्रदूषक तत्व पृथ्वी की निचली सतह पर रहेंगे जो आबोहवा को और जहरीला बनाएंगे। दीपावली पर पटाखे और पराली भी इसमें जुड़ी तो हालात तब खराब हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण पर अधिक जोर देना होगा। हालांकि पराली के मामलों में करनाल में जहां जलाए जाने के मामले सुनाई दे रहे हैं वहीं पंजाब में भी 40 प्रतिशत मामलों में वृद्धि बताई जा रही है। वहीं पंजाब में भी 40 प्रतिशत मामलों में वृद्धि बताई जा रही है। प्रदूषण पर गठित कमेटी के चेयरमैन भूरेलाल ने कहा कि 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाएगा और हम औद्योगिक इलाकों में अधिक ध्यान दे रहे हैं। इन इलाकों में रबर, प्लास्टिक को जलाने, ईंधन के तौर पर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ईंधन का इस्तेमाल न करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सभी औद्योगिक इकाइयां सही ईंधन का इस्तेमाल करें इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसमें अलावा जीआरएपी के सभी प्रावधान भी लागू किए जा रहे हैं।

एनसीपी ने नहीं चुकाया बाल ठाकरे का एहसान, वर्ली सीट पर अदित्य के सामने उतारा उम्मीदवार

वर्ली(एजेंसी)। इस बार महाराष्ट्र की ही नहीं पूरे देश की निगाहें वर्ली विधानसभा सीट पर लगी हैं। पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनावी दंगल में उतरा है और पार्टी ने उसके लिए इस सीट को सुरक्षित माना है। बाल ठाकरे के पोते और युवा शिवसेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताती है। शिवसेना को उम्मीद थी कि एनसीपी बाला साहेब के पोते के आगे उम्मीदवार नहीं उतारेगी। 2006 में जब सुप्रिया सूले ने पहली बार राज्यसभा चुनाव लड़ने का एलान किया था तो बाल ठाकरे ने यह कहकर उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था कि उन्हें गर्व है कि महाराष्ट्र की बेटी दिल्ली जा रही है। मगर आदित्य को वर्ली सीट थाली में परोस कर नहीं दी जा रही। एनसीपी और कांग्रेस ने यहां से अपना एडवोकेट सुरेश माने को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। 1990 से शिवसेना यह सीट जीतती आ रही है। सिर्फ 2009 में यहां उलटफेर हुआ जब एनसीपी के उम्मीदवार अहिर सचिन मोहन ने शिवसेना के चेंबुरकर को हरा दिया था। हालांकि 2014 के चुनाव में शिव सेना के सुनील गोविंद शिदे ने 23 हजार के अंतर से यह सीट सचिन मोहन को हरा कर जीत ली थी। शिवसेना वर्ली में उलटफेर करने वाले एनसीपी नेता अहिर सचिन मोहन को पार्टी में शामिल कर अपनी पकड़ मजबूत कर लेने का दावा कर रही है। शिवसेना की नजरें मुख्यमंत्री पद पर हैं। उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं कि उन्होंने पिता से वादा किया था कि वह एक दिन शिव सैनिक को महाराष्ट्र का सीएम जरूर बनाएंगे।

अभिजीत की मां ने देश की स्थिति पर जताई चिंता, कहा- सरकार नहीं सुन रही किसी की बात

नेशनल डेस्क। भारतीय-अमरीकी अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमरीका के अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तीनों को वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों के लिये यह पुरस्कार दिया जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया में 58 वर्षीय बनर्जी ने कहा कि पुरस्कार के लिए चुना जाना काफी 'सुखद' अनुभव है। वहीं समाजिक विज्ञान की प्रोफेसर रह चुकीं अभिजीत की मां निर्मला बनर्जी ने इसपर खुशी जताते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसी की बात नहीं सुन रही और आगे भी नहीं सुनेगी। स्थिति बेहद चिंताजनक है। निर्मला ने कहा कि अभिजीत के लिए आज का दिन किसी आम दिन जैसा ही है। मैं अपनी बहू के लिए भी बहुत खुश हूं। वह अभी युवा हैं और यह उनके लिए बड़ी बात है। निर्मला बनर्जी ने अमत्र्य सेन के बारे में कहा कि हमारे परिवार के सेन के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। वह हमारे बेहद करीबी शख्स हैं। बनर्जी व डुफलो को एमआईटी की बधाई। अभिजीत बनर्जी के अनुसार सरकार द्वारा तेजी से समस्या की पहचान करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरा (प्रदर्शन) कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से अर्थव्यवस्था बहुत खराब कर रही है। भारत में एक बहस चल रही है कि कौन सा आंकड़ा सही है और सरकार का खासतौर से यह मानना है कि वो सभी आंकड़े गलत हैं, जो असुविधाजनक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार भी अब यह मानने लगी है कि कुछ समस्या है। बनर्जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से धीमी हो रही है। कितनी तेजी से, यह हमें नहीं पता है, आंकड़ों को लेकर विवाद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह तेज है। उन्हें ठीक-ठीक नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। उनके विचार में जब अर्थव्यवस्था 'अनियंत्रित गिरावट' की ओर जा रही है, ।

गोवा की तर्ज पर दिल्ली के होटल में चल रहा था कसीनो, 58 गिरफ्तार

नई दिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली में भी गोवा की तर्ज पर वसंतकुंज साउथ जैसे पॉश इलाके में एक होटल के बेसमेंट में हाई प्रोफाइल कसीनो चल रहा था। कैसीनो ऐसा जहां पर हुक्काबार, शराब से लेकर सब कुछ का इंतजाम था। लेकिन वसंत कुंज साउथ पुलिस ने एक सूचना के बाद छापेमारी कर संचालक सहित 58 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को कसीनो से 11 लाख रुपए नकदी और 84 लाख की कीमत के विशेष प्रकार के 6 हजार प्लास्टिक टोकन, 65 से ज्यादा मोबाइल, 5 सेट टेबल, 7 हुक्का और बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई है। साउथ वेस्ट जिले के डीसीपी देवेंद्र आर्या ने बताया कि घिटोरनी एमबी रोड स्थित होटल इम्पीरियल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल के बेसमेंट में बड़े स्तर पर हाई प्रोफाइल कसीनो चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली समेत बाहर के कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल होंगे। सूचना के बाद एसीपी रमेश कुमार के देखरेख व एसएचओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एसआई रोहित और भगवान सिंह समेत अन्य की टीम बनाई गई। उसके बाद 13 अक्तूबर की देर रात होटल को चारों तरफ से पुलिस की टीम ने घेर लिया। उसके बाद मुखबिर के इशारे के बाद पुलिस ने छापेमारी की तो बेसमेंट में 60 लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में के बाद पुलिस ने आयोजकों सहित 58 लोगों के खिलाफ के स दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल पार्टी के आयोजकों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी में नेपाली मूल की 5 लड़कियां भी शामिल थी। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं की है। 3 कारोबारी दास साजिद,भक्ति और जगजीत हैं। यह तीनों होटलों में इस तरह का अक्सर पार्टी का आयोजन करवाते रहते हैं। इस होटल में भी पार्टी के लिए एक माह से तैयारी चल रही थी। होटल के बेसमेंट को जिम के मालिक साजिद ने बुक किया था, जबकि पार्टी का आयोजन में तीनों दोस्त दिल्ली-एनसीआर में हर वर्ष पार्टी का आयोजन करते हैं। जगजीत फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी की माने तो होटल के अंदर बेसमेंट में बने कसीनो को बिल्कुल गोवा के तर्ज पर तैयार किया गया था। पुलिस को कसीनो में 84 करोड़ की कीमत के टोकन मिले हैं, जो गोवा की तरह वहां चलने वाले कसीनो में चीप से तैयार किए गए थे। इस कसीनो व पार्टी के अंदर विशेष लोगों को ही बुलाया गया था। आयोजकों ने कसीनों में विशेष प्रकार के टेबल भी रखवाए हुए थे। पुलिस को इस कसीनो से 5 विशेष टेबल भी बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ के बाद सामने आया है कि तीनों आयोजक दोस्तों ने दिवाली से पहले 13 दिन में 6 ओर पार्टी का अलग-अलग जगहों पर आयोजन किया जाना था। जिसके लिए आरोपी सभी तैयारी कर चुके थे। पार्टी के लिए आरोपियों ने विशेष ग्रुप भी तैयार कर लिए थे। जगह की बुकिंग की जा रही थी। आयोजन ने एक दिन पहले भी सभी को खेलने के लिए आमंत्रण भेजना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मोदी सरकार का यकीन विचारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में : येचुरी

नई दिल्ली(एजेंसी)। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर विचारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और शिक्षण संस्थाओं पर हमलों में यकीन करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है जो आलोचनात्मक विचारों को नष्ट करता हो। येचुरी ने देश में विपरीत विचारधारा वाले लोगों के लिए बार बार खतरे उत्पन्न किए जाने का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा, आरएसएस भाजपा की सरकार विचारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और विश्वविद्यालयों पर हमले कराने में यकीन करती है। इस सरकार ने ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसमें विरोधी विचारों को नष्ट किया जा रहा है। हमारा संविधान वैचारिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह बात भाजपा आरएसएस की सरकार के लिए संकट उत्पन्न करती है। जेएनयू के पूर्व छात्र अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने और आर्थिक मंदी से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए येचुरी ने कहा कि सरकार को गरीबों के भरण पोषण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त बनाने पर प्राथमिकता के साथ ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले अपने नागरिकों का भरण पोषण सुनिश्चित हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले खाद्यान्न पर सब्सिडी बढ़ाई जाये। लेकिन मोदी सरकार हमारे सामाजिक तानेबाने को नष्ट करने और प्रचार के तमाशे में व्यस्त है। प्रचार के तमाशे में व्यस्त हैं। येचुरी ने ट्वीट कर कहा कि देश में भुखमरी की समस्या गहरा गई है। अर्थव्यवस्था न सिर्फ आंकड़ों के आधार पर संकट में है बल्कि लोगों की गुजर बसर भी प्रभावित हुई है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है।

हिंदू पक्ष के वकील बोले- अयोध्या में 50-60 मस्जिदें, मुस्लिम कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज

अयोध्या(एजेंसी)। अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई अब अंतिम दौर में चल रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं। मंगलवार को हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील के. परासरण ने कहा कि मुस्लिम कहीं और भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अयोध्या में 56-60 मस्जिद हैं। वह राम का जन्मस्थान है, इसे बदला नहीं जा सकता। परासरण ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी भारत के इतिहास को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट को इतिहास की गलती को ठीक करना चाहिए। एक विदेशी भारत में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि अगर सूट प्रॉपर्टी नष्ट हो गई है, तो फैसला किस पर दिया जाएगा? इस पर परासरण ने कहा कि मैं नहीं मानता मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है, लेकिन मेरी दलील है कि मंदिर हमेशा मंदिर रहता है। फिर चाहे वहां पर भवन, मूर्ति हो या नहीं। हिंदू पक्षकार महंत रामचंद्र दास के शिष्य सुरेश दास की ओर से वकील परासरण अपनी दलीलें दे रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा बुधवार को अपनी दलील रखेगा। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा बुधवार को अपनी दलील रखेगा।बुधवार को अपनी दलील रखेगा। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा बुधवार को अपनी दलील रखेगा। निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन की मां की मृत्यु हो जाने के कारण वह अदालत नहीं पहुंच सके।

श्रीनगर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में ली गई फारूक अब्दुल्ला की बेटी और बहन

नेशनल डेस्क(एजेंसी)। पुलिस ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की बेटी और बहन समेत छह महिलाओं को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि महिलाएं जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने और राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों में बांटने के विरोध में प्रदर्शन कर रही थीं। महिला प्रदर्शनकारियों के एक समूह का नेतृत्व कर रहीं अब्दुल्ला की बहन सुरैया और उनकी बेटी साफिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बांह पर काली पट्टी बांधकर तख्तियां पकड़े प्रदर्शन कर रहीं इन महिलाओं को पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोका और शांतिपूर्वक लौट जाने के लिए कहा। महिलाओं ने जाने से मना किया और प्रदर्शन जारी रखते हुए धरने पर बैठ गईं। महिला सीआरपीएफ जवानों ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहनों में बैठाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कवरेज के लिए आए मीडिया को बयान वितरित करने से रोकने का प्रयास भी किया। बयान में कहा गया कि हम कश्मीर की महिलाओं ने भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 को हटाए जाने तथा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एकतरफा फैसले को अस्वीकार कर दिया है। नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए । महिलाओं ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से धोखा और अपमान मिला है। उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल रिहा करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विसैन्यीकरण की भी मांग की। बयान में कहा गया है हम कश्मीर में झूठे एवं गुमराह करने वाले प्रचार के लिए राष्ट्रीय मीडिया के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। स्था में अजीतगढ़ के राजकीय अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे गंभीर घायल अवस्था में जयपुर रैफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थोई पुलिस थाने से गंभीर घायल अवस्था में जयपुर में उच्चाधीन तुलसीराम अपने नए मकान के नांगल समारोह के आमंत्रण पत्र बांटने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया था और आज मौत और जिन्दगी की जंग से जूझ रहा है।

स्वदेशी हथियारों के दम पर भविष्य की जंग जीतेगी सेना: बिपिन रावत

नेशनल डेस्क(एजेंसी)।

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने एक बार फिर दोहराया कि भविष्य में संभावित जंग से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि अगली बार हम स वदेशी हथियारों से लड़ेंगे और हमारी जीत होगी। रावत ने भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारी नजर ऐसे सिस्टम पर है, जिनकी जरूरत भविष्य की जंग में होगी। हमने साइबर, अंतरिक्ष, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक टेक्नोलॉजीज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ने देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं, जिनसे सेना को काफी फायदा पहुंचा है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम अगला लड़ाई जब भी लड़ेंगे, तो उसे जीतेंगे और ये जीत स्वदेशी हथियारों के दम पर होगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, भारतीय वायु सेना प्रमुख मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

संपादकीय

खेतों से उठता धुआं

पंजाब और हरियाणा के खेतों से निकला धुआं उत्तर भारत के आसमान पर छाने लगा है। इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी एनसीआर की पहले से ही काफी प्रदूषित हवा में कुछ और तीखापन घोल दिया है। वैसे यह हर साल ही होता है। अक्तूबर के महीने में जब खरीफ की फसल कट जाती है, तो खेतों में बच गए फसल के बाकी हिस्से को किसान जला डालते हैं। कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें रबी की फसल के लिए खेत तैयार करना होता है, इसलिए मैदान साफ करने का सबसे आसान तरीका होता है खेतों में बची पराली को जला देना। इसके कुछ छोटे-मोटे फायदे और भी होते हैं, और कुल मिलाकर इन्हीं सब के लिए हवा में जहर घोलने का काम बरसों-बरस से चल रहा है। पिछले कुछ सालों से इस पर सख्ती बरती जानी शुरू हुई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने पराली जलाने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया है। इस सबसे उम्मीद बनी थी कि इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम होंगी। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। पंजाब में इस साल पराली जलाने की घटनाएं 45 फीसदी तक बढ़ गई हैं। पंजाब प्रदूषण बोर्ड के रिमोट सेंसिंग केंद्र के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल 11 अक्तूबर तक पराली जलाने की 435 घटनाएं हुई थीं, इस साल इस समय तक ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़कर 630 हो गई है। हरियाणा से ऐसे आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन आशंका यही है कि वहां भी ऐसी घटनाएं बढ़ी ही होंगी। हरियाणा में इस समय विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और प्रशासन के लिए वह सबसे बड़ी प्राथमिकता है, शायद इसलिए भी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की बड़े पैमाने पर कोशिश शुरू नहीं हुई है। हर साल जब पराली का धुआं राजधानी और इसके आस-पास के इलाके पर छाता है, तो हम किसानों को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देते हैं। साथ ही, उन्हें यह सबक भी दिया जाता है कि पराली को जलाने की बजाय उसके इस्तेमाल के और कई अच्छे विकल्प हैं। बेशक ऐसे विकल्प हैं, पर सच यही है कि उन्हें अभी न तो किसानों तक पहुंचाया जा सका है और न ही किसानों को आश्वस्त किया जा सका है कि ऐसे विकल्प उनके लिए आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इस मामले में पाबंदी और जुर्माने के साथ ही रचनात्मक सक्रियता की जरूरत है, जो कहीं नहीं दिखती। वैसे पराली जलाने की समस्या भारत की ही नहीं, दुनिया के कई देशों की है। चीन में तो यह समस्या है ही, अमेरिका और फ्रांस तक इससे परेशान रहे हैं। दुनिया भर का जिक्र इसलिए जरूरी है कि समस्या का एक कारण फसल कटाई की आधुनिक तकनीक भी है, जिससे पौधों का एक बड़ा हिस्सा खेतों में लगा रह जाता है। कई देशों के किसानों ने वैकल्पिक तरीकों को भी अपनाया है। जाहिर है, ऐसे तरीके किसान तभी अपनाते हैं, जब उसमें उन्हें कोई फायदा दिखे। ऐसे देशों की सीख भी काम की हो सकती है। हमारे देश में खेती जिस तरह से घाटे का सौदा बनी है, उसमें यह उम्मीद व्यर्थ है कि किसान खेतों को पराली मुक्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम या संसाधन खर्च करेंगे। वैकल्पिक तरीकों को सीखने की उनकी क्षमता भी सीमित है। यह काम सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को ही करना होगा।

विकास के साथ जीवन की गुणवत्ता भी जरूरी

भरत झुनझुनवाला

बीते बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर, जिसे कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है, को लगभग 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 43 प्रतिशत कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अमीरों का दायित्व बनता है कि देश की जरूरतों में अधिक योगदान करें। बीते माह उन्होंने अपने कदम को पूरी तरह वापस ले लिया और कंपनियों द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर को घटाकर लगभग 33 प्रतिशत कर दिया है। इस उलटफेर से स्पष्ट होता है कि आयकर की दर का आर्थिक विकास पर प्रभाव असमंजस में है। यदि आयकर बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव सकारात्मक भी पड़ सकता है और नकारात्मक भी। यदि राजस्व का उपयोग घरेलू माल की खरीद से निवेश करने के लिए किया गया, जैसे देश में बने सीमेंट और बजरी से गांव की सड़क बनायी गयी तो इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा। इसके विपरीत यदि उसी राजस्व का उपयोग राफेल फाइटर प्लेन खरीदने के लिए अथवा सरकारी कर्मियों को ऊंचे वेतन देने के लिए किया गया तो प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है। कारण यह कि राफेल फाइटर प्लेन खरीदने से देश की आय विदेश चली जाती है। जैसे गुब्बारे की हवा निकाल दी जाए। लेकिन इसके पीछे जो आर्थिक गणित है वह यह है कि यदि सरकारी कर्मियों को ऊंचे वेतन दिए जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी माल जैसे स्विट्जरलैंड की बनी चॉकलेट खरीदने में अथवा विदेश यात्रा में खर्च हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास की दर पुनः गिरती है। देश में मांग उठ रही है कि व्यक्तियों द्वारा देय आयकर में भी कटौती की जाए। इसका भी प्रभाव सकारात्मक पड़ सकता है अथवा नकारात्मक। इतना सही है कि आयकर घटाने से करदाता के हाथ में अधिक रकम बचेगी। जैसे करदाता पहले यदि 100 रुपये कमाता था और उसमें से 30 रुपये आयकर देता था तो उसके हाथ में 70 रुपये बचते थे। यदि आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर दी जाए तो करदाता के हाथ में अब 75 रुपये बचेंगे। वह पहले यदि 70 रुपये का निवेश कर सकता था तो अब 75 रुपये का निवेश कर सकेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बची हुई रकम का निवेश ही किया जाएगा। उस रकम को वह देश से बाहर भी भेज सकता है। बताते चलें कि यदि देश में आयकर की दर घटा दी जाए तो भी यह निवेश करने को पर्याप्त प्रलोभन नहीं है क्योंकि अबू धाबी जैसे तमाम देश हैं जहां पर आयकर की दर शून्यप्राय है। मनिपाल ग्लोबल एजुकेशन के टी. वी. मोहनदास पाई के अनुसार देश से अमीर बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। वे भारत की नागरिकता त्याग कर अपनी पूंजी समेत दूसरे देशों को जा रहे हैं और उन देशों की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं। पाई के अनुसार इसका प्रमुख कारण टैक्स कर्मियों का आतंक है। उनके अनुसार आज करदाता महसूस करता है कि उसे टैक्स कर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। मानना है कि वर्तमान सरकार कंप्यूटर तकनीक के उपयोग से आयकरदाताओं और टैक्स अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क कम कर रही है जो कि सही दिशा में है लेकिन इसके बाद जब जांच होती है अथवा अपील की प्रक्रिया होती है तो करदाता और टैक्स अधिकारियों का आमना-सामना होता ही है। मूल बात यह है कि वर्तमान सरकार टैक्स अधिकारियों को ईमानदार और करदाताओं को चोर की तरह देखती है। सरकार का यह प्रयास बिल्कुल सही है कि देश में तमाम उद्यमी हैं जो देश के बैंकों की रकम को लूट कर जा रहे हैं अथवा टैक्स की चोरी कर रहे हैं। लेकिन एक चोर को दूसरे चोर के माध्यम से पकड़ना कठिन ही है। मनु स्मृति में कहा गया है कि 'राजा के कर्मी मुख्यतः चोर और फरेबी होते हैं और वे जनता का धन लूटते हैं, राजा इनसे अपनी जनता की रक्षा करे।' यानी मनु स्मृति के अनुसार सरकार के कर्मी मूलतः चोर होते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की दृष्टि में सरकार के कर्मी ईमानदार हैं और करदाता चोर हैं। अतः कंप्यूटर तकनीक से जो सुधार किया जा रहा है, उससे कर्मियों का मूल भाव बदलता नहीं दिखता है। परिणाम यह है कि टैक्स के आतंक के चलते देश से अमीरों का पलायन जारी है। अमीरों के पलायन का दूसरा प्रमुख कारण जीवन की गुणवत्ता बताया जा रहा है। देश में वायु की गुणवत्ता गिरती जा रही है। मेरे एक मित्र दिल्ली में रहते थे। उनकी पत्नी का वजन बिना किसी कारण के 45 किलो से घटकर 25 किलो हो गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली को छोड़ा और देहरादून में आकर बसे। बिना किसी दवाई के उनकी पत्नी का वजन पुनः बढ़ गया। वायु की घटिया क्वालिटी के कारण अमीर अपने देश में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार ट्रैफिक की समस्या है, जिसके कारण वे यहां नहीं रहने चाहते हैं। इस दिशा में सरकार का प्रयास उल्टा पड़ रहा है। जैसे सरकार ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित जहरीली गैसों के मानकों में हाल में छूट दे दी है, उन्हें वायु प्रदूषित करने का अवसर दे दिया है। इस छूट का सीधा परिणाम यह है कि बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादन लागत कम होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लेकिन उसी छूट के कारण वायु की गुणवत्ता में गिरावट आएगी और देश के अमीर यहां से पलायन करेंगे और विकास दर घटेगी, जैसा हो रहा है। इसी प्रकार सरकार ने गंगा के ऊपर बड़े जहाज चलाने का निर्णय लिया है। सीधे तौर पर बड़े जहाज चलेंगे, ढुलाई का खर्च कम होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लेकिन इन्हीं बड़े जहाजों से गंगा का पानी प्रदूषित होगा, गंगा का सौन्दर्य खंडित होगा और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। अतः सरकार को किसी निर्णय को लेते समय जीवन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा और पर्यावरण को बोझ समझने के स्थान पर पर्यावरण की रक्षा के इस आर्थिक लाभ का भी मूल्यांकन करना होगा। तीसरा बिंदु सामाजिक है। अमीर व्यक्ति चाहता है कि उसे वैचारिक स्वतंत्रता मिले। वह अपनी बात कह सके। लेकिन बीते समय में देश में स्वतंत्र विचार को हतोत्साहित किया गया है। जो व्यक्ति सरकार की विचारधारा से विपरीत सोचता है, उसके ऊपर किसी न किसी रूप से दबाव डाला जा रहा है। इन तमाम कारणों से अमीरों को भारत में रहना पसंद नहीं आ रहा है और वह देश से पलायन कर रहे हैं। वित्तमंत्री द्वारा टैक्स कॉर्पोरेट कम्पनियों द्वारा अथवा व्यक्तियों द्वारा जो आयकर में कटौती की गयी है अथवा जो शीघ्र किये जाने की संभावना है, उससे देश के आर्थिक विकास को कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि मूल समस्या सांस्कृतिक है। देश ने जो नौकरशाही को ईमानदार, पर्यावरण की हानि को आर्थिक विकास का कारक और वैचारिक विभिन्नता को नुकसानदेह दृष्टि से देख रखा है, उसका सीधा परिणाम है कि देश के अमीर देश को छोड़कर जा रहे हैं और देश की आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ रही है।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

आज के ट्वीट

स्थिति

पहले हरियाणा में सरकारी भर्ती का मतलब होता था रिश्वतखोरी और युवाओं से लूट। नौकरियों के लिए जितनी तरह के खेल होते थे, उन्होंने यहां के कई नेताओं को जेल तक पहुंचाया है। लेकिन ये स्थिति अब बदल चुकी है : पीएम मोदी

--बीजेपी

ज्ञान गंगा

अहंकार

ओशो/यह असंभव है। अहंकार का त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार केवल एक विचार है- उसमें कोई सार नहीं है। अहंकार एक तरह का अभाव है। अहंकार इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। जिस क्षण तुम स्वयं को जान लेते हो, कोई अहंकार नहीं पाओगे। तुम्हें बार-बार कहा गया है- ''अपने अहंकार को मारो'-और यह वाक्य साफ तौर पर बेतुका है, क्योंकि जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज का त्याग करने से पहले उसकी उपस्थिति का पक्का कर लेना चाहिए पर आरंभ से ही इसके विरोध में ना चले जाओ। यदि तुम इसका विरोध करते हो तो तुम इसको गहराई से नहीं देख सकोगे। अहंकार के ढंगों को देखो, यह कैसे काम करता है, आखिर कैसे यह संचालित करता है। और तुम हैरान हो जाओगे; जितने गहरे तुम इसमें जाते हो यह उतना ही दिखाई नहीं पड़ता। ''अहंकार' वो है जिसे तुम एकत्रित करते हो; अहंकार तुम्हारी उपलब्धि है। अहंकार का समर्पण नहीं करना होता, उसका साक्षी बनना होता है। यही है ''रिस्पेक्ट'' का अर्थ। इसका अर्थ यह नहीं है जो प्रचलन में है- ''आदर'। नहीं-रिस्पेक्ट का साधारण सा अर्थ है- ''री-स्पेक्ट', फिर से देखना। यही है इसका शाब्दिक अर्थ; इसमें आदर जैसे शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। ''स्पेक्ट' का अर्थ है देखना; ''री' का अर्थ है दोबारा। यदि तुम री-स्पेक्ट करते हो, यदि तुम फिर से देखते हो और अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हो, तो तुम एक जगह पाओगे जहां से तुमने स्वयं को खोना और अहंकार को अर्जित करना आरंभ किया था। वो पल रोशनी का एक पल होता है, क्योंकि एक बार यदि तुमने देख लिया कि अहंकार क्या है, तब खेल समाप्त हो जाता है। तो मैं तुम्हें यह नहीं कह सकता कि अहंकार को गिरा दो क्योंकि इसका तो अर्थ हुआ कि मैंने तुम्हारे अहंकार की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। और तुम उसे गिरा कैसे सकते हो-जब कि तुम ही वह हो। इस क्षण में तुम ही अहंकार हो। स्वयं को तो तुमने कहीं पीछे अतीत में छोड़ दिया है। यह समझने योग्य एक बहुत ही आधारभूत बात है-अहंकार अपने शिखर पर आ जाए, वह मजबूत हो जाए, और एक अखंडता हासिल कर ले-केवल तभी तुम उसे पिघला सकोगे। एक दुर्बल अहंकार को पिघलाया नहीं जा सकता। और यह एक समस्या बन जाता है।

आज का राशिफल

मेष बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी।

वृषभ पारिवारिक व व्यावसायिक समस्याएं रहेंगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

मिथुन सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक योजना सफल होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ के तनाव मिलेंगे।

कर्क बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जारी प्रयास सफल होंगे। वाणी की सौम्यता बनाये रखें। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। पिता या उच्चाधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।

कन्या जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

तुला राजनैतिक महात्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजना सफल होगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

वृश्चिक आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। प्रियजन भेंट संभव।

धनु पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। जारी प्रयास सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

मकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

कुम्भ व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। नेत्र विकार की संभावना है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मीन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। सृजनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना पड़ सकता है। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कार्यों में खर्च करना पड़ सकता है।

प्राथमिकी दूसरे राज्य में भेजे जाने पर सवाल

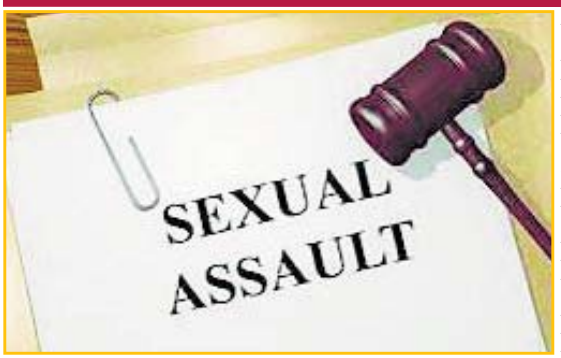

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र/ अनूप भटनागर

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का कानून बनने के छह साल बाद अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रोचक मामला आया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के खिलाफ कथित रूप से यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी जांच के लिये दूसरे राज्य को भेज दी। सवाल उठता है कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम कानून के तहत शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी उच्च न्यायालय किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? यह विवाद भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात महिला अधिकारी से संबंधित है। दोनों ही अधिकारी तमिलनाडु में तैनात हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न की महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष विचारार्थ होने के दौरान ही मामला पुलिस में भी पहुंच गया था। कार्यस्थल में उत्पीड़न की रोकथाम और इस बारे में मिलने वाली शिकायतों के समाधान के लिये ही 2013 में सरकार ने एक कानून बनाया। लेकिन इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 1997 में राजस्थान के बहुचर्चित विशाखा प्रकरण में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिये व्यापक निर्देश दिये थे और कहा था कि इन पर अंकुश के लिये नया कानून बनने तक ये निर्देश प्रभावी रहेंगे। शीर्ष अदालत ने अगस्त 1997 में इस प्रकरण में अपने फैसले में कहा था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। इन अधिकारों में समता का अधिकार, कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।

न्यायालय ने महिलाओं के संरक्षण के लिये विशेष समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था ताकि ऐसी शिकायत का निदान किया जा सके। चेन्नई में पुलिस अधीक्षक स्तर की इस महिला अधिकारी की शिकायत पर तत्काल ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत जांच के लिये आंतरिक समिति गठित की गयी थी। महिला अधिकारी का आरोप था कि आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी एक साल से उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इस शिकायत में लगाये गये आरोपों की जांच के लिये पुलिस विभाग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सीमा अग्रवाल की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति गठित की थी। इस जांच समिति ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसे तमिलनाडु की सीबी-सीआईडी को मामला दर्ज करके जांच के लिये भेज दिया था। उसने इसी आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी।

महिला अधिकारी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जांच समिति पुनर्गठित करने और आईपीएस अधिकारी का तबादला करने का अनुरोध किया था। इसी बीच, महिला अधिकारी की शिकायत पर तमिलनाडु पुलिस की अपराध शाखा से इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कर ली थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान महिला अधिकारी जांच की कार्यवाही और प्राथमिकी को केरल या किसी अन्य पड़ोसी राज्य या दिल्ली स्थानांतरित करने पर सहमत हो गयी थी लेकिन आईपीएस अधिकारी का तर्क था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानून के तहत कार्यवाही को स्थानांतरित करने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। राज्य सरकार भी इसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन, उच्च न्यायालय ने इस मामले की प्रकृति और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसे तमिलनाडु से तेलंगाना स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया।

इस मामले में विवाद का केन्द्र बने इस आईपीएस अधिकारी का जून महीने में तबादला कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को इस सारे मामले को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिये तेलंगाना स्थानांतरित कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को न्याय के हित में आदेश देने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरह उच्च न्यायालय राज्य के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ अदालतों में लंबित किसी मामले या अपील को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच तथा सुनवाई के लिये मुकदमे या प्रकरण अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी अन्य जिले में स्थानांतरित कर सकता है। शीर्ष अदालत अगले सप्ताह इस प्रकरण पर विचार कर सकती है।

खाद्य मंत्रालय की विदेश मंत्रालय से गुहार, कहा- नहीं रख पाएंगे इतना चावल-गेहूं, दान कर दीजिए

नई दिल्ली(एजेंसी)।

भारतीय खाद्य निगम में अनाज बहुतायत में होने के चलते सरकार इसके भंडारण के खर्चे के कम करने और नुकसान से बचने के लिए देशभर में जरुरत से ज्यादा अनाज भंडार को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए खाद्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह अतिरिक्त अनाज के भंडार को योग्य देशों को मानवीय सहायता के रूप में देने के विकल्प के रूप में विचार करे। सूत्रों के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि वो एफसीआई के पास उपलब्ध अतिरिक्त भंडार से गेहूं और चावल को जीटूजी (सरकार से सरकार) के जरिए योग्य देशों को मानवीय सहायता देने की संभावनाओं का पता लगाए। इस साल की शुरुआत में सचिवों की एक समिति ने भी सिफारिश की थी कि विदेश मंत्रालय योग्य देशों की सहायता के रूप में गेहूं की पेशकश की संभावना का पता लगाए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग मंत्रालय ने भी पिछले दो सालों में कम से कम दो बार विदेश मंत्रालय से इस तरह का अनुरोध किया था। सूत्रों ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा गेहूं और चावल की खरीद में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। इससे एफसीआई में गेहूं और चावल का अतिरिक्त भंडार और बढ़ गया। भंडारण मानदंडों के मुताबिक एक जुलाई को सेंट्रल पूल में खाद्यान्न की कुल जरुरत 411.20 लाख टन थी मगर एक सितंबर को सेंट्रल पूल में अनाज का भंडारण 669.15 लाख टन था। इसमें 254.25 लाख टन चावल और 414 लाख टन गेहूं थे।

पीएम किसान सम्मान निधिः पिछले लाभार्थियों को भी नहीं मिल रही रकम

नई दिल्ली(एजेंसी)।

किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए शुरू की गई पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना बुरी तरह अटक गई है। सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक इस योजना के लिए 7.45 करोड़ किसानों की पहचान की जा चुकी है लेकिन तीसरी किस्त देने से पहले इनका सत्यापन नहीं हो पा रहा। ऐसे में सिर्फ 1.74 करोड़ किसानों को ही ताजा किस्त मिल सकी है। कुल 5.7 करोड़ यानी हर 4 में से 4 किसान सरकारी मदद से वंचित हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की गई योजना तहत पहली किस्त में 6.78 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए पहुंचे लेकिन दूसरी किस्त में यह संख्या घटकर 5.19 करोड़ हो गई। इस बार आधार की अनिवार्यता कर दिए जाने के बाद तो लाभार्थी किसान जैसे पूरी तरह गायब हो गए हैं। तीसरी किस्त तक लाभार्थी किसानों की संख्या 5.7 करोड़ कम हो गई है। शुरूआत में 2 हैक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को ही इस योजना में शामिल किया गया था लेकिन दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद सभी किसानों को योजना में शामिल कर लिया गया। इसके तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में 6000 रुपए देना प्रस्तावित हैं। पहली 2 किस्तें देने के बाद सभी लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार के जोड़े जाने की प्रक्रिया भी काफी दुरूह बना दी गई है। इसमें सरकारी तंत्र बहुत ढिलाई भी कर रहा है। मध्य प्रदेश के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। यहां कुल 41.02 लाख किसान लाभार्थी के रूप में दर्ज किए गए थे। इनमें से 34.31 लाख किसानों को पहली किस्त जारी हुई। दूसरी किस्त में यह संख्या घटकर 12.23 लाख हो गई। तीसरी किस्त में अब तक महज 26 किसानों को ही यह रकम जारी हो पाई है।

भारती एयरटेल के एमडी ने कहा- मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाने की जरूरत

नई दिल्ली(एजेंसी)।

भारती एयरटेल के एमडी और सीईओ (भारत एवं दक्षिण एशिया) गोपाल विट्टल ने मंगलवार को कहा कि मोबाइल सेवाओं की मौजूदा दरें जारी नहीं रखी जा सकतीं, इन्हें बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहुंचे विट्टल ने मीडिया से बातचीत में ये ऐसा कहा। उनका कहना था कि अगले राउंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रस्तावित कीमत भी काफी ज्यादा है, यह 5जी बिजनेस के लिए वहन करने योग्य नहीं। विट्टल के मुताबिक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की उम्मीदें पूरी करने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री की सेहत दुरुस्त और जोशपूर्ण होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री में निवेश नहीं आएगा तो हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। मनचाहे नतीजे पाने के लिए यह दो जिम्मेदारियां निभाने का वक्त है, एक कंपनी के प्रति और दूसरी देश के प्रति। टेलीकॉम सेक्टर की समस्याएं सुलझाने के लिए संबंधित पक्ष दृष्टिकोण में बदलाव लाएं तो यह सेक्टर क्रांति ला सकता है। रिलायंस जियो द्वारा दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए ग्राहकों से 6 पैसे प्रति मिनट लेने के फैसले की विट्टल ने निंदा की। उन्होंने कहा कि इंटरकनेक्शन यूजेज चार्ज (आईयूसी) टैरिफ का हिस्सा नहीं, बल्कि ऑपरेटर्स के चार्ज हैं। पिछले 20 साल से आईयूसी चार्ज ऑपरेटर ही वहन कर रहे हैं।

एचडीएफसी ने होम लोन पर ब्याज दर घटाई, पुराने लोन पर भी मिलेगा फायदा

मुंबई(एजेंसी)।

आवास ऋण देने वाली प्रमुख वित्तीय कंपनी एचडीएफसी ने अपने फ्लोटिंग कर्ज पर ब्याज दरों में 0.10 फीसदी कटौती की है। इसके साथ ही एचडीएफसी भी अब उन ऋणदाताओं की सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने हाल के दिनों में अपने ऋण पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। इस कटौती का लाभ एचडीएफसी के मौजूदा और नया ऋण लेने वाले दोनों ग्राहकों को मिलेगा। इससे वेतनभोगी ग्राहकों के लिए ऋण की ब्याज दर निचले स्तर पर 8.25 फीसदी और ऊंचे स्तर पर 8.65 फीसदी रह जाएगी। यह कटौती 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2019 से नीतिगत दर यानी रेपो दर में कुल मिलाकर 1.35 फीसदी की कटौती की है। उसके बाद से कई बैंक आदि अपनी ब्याज दरों में कटौती कर चुके हैं। आवास ऋण के क्षेत्र में एचडीएफसी के बड़े प्रतिद्वंद्वी भारतीय स्टेट बैंक ने भी पिछले सप्ताह अपने ऋण पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की थी। इसके बाद स्टेट बैंक की एक साल की सीमांत लागत आधारित ऋण की ब्याज दर (एमसीएलआर) 8.05 फीसदी रह गई। स्टेट बैंक के कुछ कर्ज अभी भी एमसीएलआर से जुड़े हैं। जुलाई से बैंक के नये आवास ऋण रेपो दर से जुड़े हैं। एचडीएफसी के प्रवक्ता ने कहा, ''हमने अपने आवास ऋण पर खुदरा प्रधान ऋण दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी।

संक्षिप्त समाचार

मारुति का 2018-19 में सीएसआर गतिविधियों पर 154 करोड़ रुपए का निवेश

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों पर 2018-19 में 154 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। मारुति की सीएसआर पहल सामुदायिक विकास, सड़क सुरक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित रही। मारुति के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी केनिचि आयुकावा ने बयान में कहा, परियोजनाओं का चयन जरूरत का आकलन करके और हितधारक से परामर्श के आधार पर किया गया है।÷ कंपनी ने कहा कि उसने हरियाणा और गुजरात के 26 गांवों में सामुदायिक विकास के प्रयास किए। इसमें पानी एवं स्वच्छता , शिक्षा और सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा, कंपनी ने 110 से ज्यादा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भी समर्थन किया। मारुति ने कहा कि 2018-19 में कंपनी ने सात ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और 16 सड़क सुरक्षा केंद्रों में लगभग 4,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया।

लक्ष्मी विलास बैंक, सिंडिकेट पर लगा जुर्माना

मुंबई। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपए और सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संपत्ति वर्गीकरण और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले नियमों के उल्लंघन को लेकर ये जुर्माने लगाए गए हैं। आरबीआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) को लेकर जारी केंद्रीय बैंक के नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने 14 अक्टूबर को इस आशय का आदेश जारी किया। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसके बारे में जानकारी देने को लेकर जारी रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।

सोना 200 रुपये, चांदी 450 रुपये मजबूत

नई दिल्ली । दिवाली और धनतेरस से पहले जेवराती मांग आने से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना मंगलवार को 200 रुपये चमककर 39,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और चाँदी 450 रुपये की छलांग लगाकर करीब एक सप्ताह के उच्चतम स्तर 47,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। विदेशों में दोनों कीमती धातुओं में रही मामूली गिरावट का असर स्थानीय बाजार पर नहीं दिखा। लंदन एवं न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के अनुसार, सोना हाजिर 0.1 प्रतिशत लुढ़ककर 1,490.70 डॉलर प्रति औंस रह गया। दिसंबर का अमेरिकी सोना वायदा 1.20 डॉलर चढ़कर 1,498.80 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि ब्रेक्जिट पर इस सप्ताह के अंत में होने वाली बैठक से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण आज सोने में मामूली गिरावट देखी गयी। गुरुवार और शुक्रवार को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली बैठक में यह तय होगा कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बिना किसी समझौते के बाहर होगा या उनके बीच कोई समझौता होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चाँदी हाजिर भी 0.2 प्रतिशत लुढ़ककर 17.61 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

पेट्रोल, डीजल के दाम 2 दिन बाद फिर घटे, कच्चे तेल में भी नरमी

नई दिल्ली । पेट्रोल और डीजल के दाम में दो दिन बाद फिर मामूली कटौती की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को देश के चार प्रमुख महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम में पांच पैसे प्रति लीटर की कटौती की। इससे पहले दो दिनों तक पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया था। उधर, अमेरिका और चीन के बीच आंशिक व्यापार करार के बीच में अटकने की आशंकाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में नरमी का रुख बना हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमशः 73.27 रुपये, 75.92 रुपये, 78.88 रुपये और 76.09 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी घटकर क्रमशः 66.41 रुपये, 68.77 रुपये, 69.61 रुपये और 70.15 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई पर ब्रेंट क्रूड के दिसंबर अनुबंध में 0.76 फीसदी की कमजोरी के साथ 58.90 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अमेरिकी लाइट क्रूड डब्ल्यूटीआई के नवंबर अनुबंध में 0.67 फीसदी की नरमी के साथ 53.63 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

पीएमसी बैंक खाताधारकों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत, खाते से निकाल सकेंगे 40 हजार रुपये

मुंबई। पीएमसी बैंकों के खाताधारकों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब खाताधारक 6 महीने में 40 हजार रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। इससे पहले यह अकाउंट से पैसे निकालने की सीमा 25 हजार तक थी। आरबीआई ने त्योहारी सीजन में बैंक के लाखों ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि अब ग्राहक छह माह में कुल 40 हजार रुपये की निकासी अपने खातों से कर सकते हैं। पहले ग्राहकों को छह महीने में सिर्फ एक हजार रुपये ही निकालने की अनुमति दी गई थी। पिछले हफ्ते आरबीआई ने बैंक पर छह महीनों का प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी थी। आरबीआई के इस कदम से लाखों ग्राहकों को राहत मिलेगी। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के कई खाताधारकों ने पीएमसी के चेयरमैन समेत 14 अधिकारियों के खिलाफ पिछले हफ्ते सायन पुलिस थाने में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई थी। ग्राहकों का आरोप था कि अधिकारियों ने उनकी रकम का दुरुपयोग किया। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर नियामकीय खामियों के चलते कई पाबंदियां लगाई हैं।

देश का पहला 5 स्टार होटल बेचने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली(एजेंसी)।

सरकार देश के ऐतिहासिक फाइव स्टार अशोका होटल के विनिवेश यानी हिस्सा बिक्री की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक (भारत पर्यटन विकास निगम) के दिल्ली स्थित होटल अशोका और होटल सम्राट के मोनेटाइजेशन की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार होटल सम्राट और होटल अशोक के मोनेटाइजेशन के लिए जल्द एडवाइजर नियुक्त कर सकती है। इन होटलों के मोनेटाइजेशन के लिए इंटरमीनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है। एडवाइजर होटल के मोनेटाइजेशन के अलग-अलग विकल्प सुझाएगा। होटल अशोका को पूरी तरह बेचने या लंबे समय के लिए लीज पर देने का विकल्प भी है। होटल अशोका के 550 कमरे 4 कन्वेंशन हॉल दिल्ली के प्राइम लोकेशन में 25 एकड़ में फैले हैं। अगर लीज पर देना हुआ तो कम से कम 60 साल के लिए लीज पर देने का विकल्प है। एडवाइजर होटल के रीकंस्ट्रक्शन के कानूनी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा। एडवाइजर को महीने भर के भीतर अपनी सिफारिश देनी होगी। एडवाइजर की सिफारिश के आधार पर ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। होटल का निर्माण देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने साल 1956 में कराया था। यह होटल संसद और राष्ट्रपति भवन के नजदीक है। इसमें 550 कमरे और 161 सूइट्स हैं। होटल में करीब 1000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसके रोजाना के संचालन में करीब 35 लाख रुपए का खर्च आता है। यहां आमतौर पर 50 फीसदी ही कमरे बुक होते है। हालांकि सर्दियों में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 80 फीसदी हो जाता है। होटल के बनने के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। भारत नया-नया आजाद हुआ था और यूनेस्को समिट को भारत में कराने को लेकर उत्सुक था। नेहरू ने 1955 में पेरिस में हुई यूनेस्को फोरम की बैठक में सुझाव दिया था कि भारत अगले साल समिट कराने के लिए तैयार है। हालांकि उस वक्त तक भारत में एक भी 5 स्टार होटल नहीं था, जहां विश्वभर से आने वाले मेहमानों को ठहराया जा सके।

आरटीआई के तहत खुलासा, बंद हुई 2000 रुपए के नोट की छपाई

नई दिल्ली(एजेंसी)।

आप परेशान होंगे कि कुछ माह से ए.टी.एम. से 2000 के नोट क्यों नहीं निकल रहे। केन्द्रीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने एक आर.टी.आई. तहत इस बात का खुलासा किया कि बड़े नोटों की छपाई बंद कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल.) के एक अधिकारी ने बताया कि अब 2000 के नए नोट प्रिंट करने में कमी कर दी गई है। इसलिए बाजार में 2000 के नोटों की कमी है। बैंकों और लोगों द्वारा भी इनकी मांग घटी है। आम आदमी को अब इतने बड़े नोट की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नोटबंदी के समय थी। उस वक्त बाजार में बड़े नोट चाहिए थे। अब 2000 के नोट से काला धन जमा होने की आशंका है। बता दें कि इस वर्ष की शुरूआत में बड़ी करंसी के नोटों की छपाई बंद करने की खबरें आई थीं लेकिन सरकार ने इससे इंकार कर दिया था। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि संभवतः उच्च मूल्य के नोटों को प्रचलन से हटाने से बहुत सारे काले धन का लेन-देन करना मुश्किल हो जाता है लेकिन यह नोटबंदी से बेहतर नीति है जो बहुत ही विघटनकारी थी। यहां आप कुछ भी बाधित नहीं कर रहे हैं। आप केवल सर्कुलेशन वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देशों ने ऐसा किया है लेकिन भारत में हमारे पास एक बहुत बड़ा अनौपचारिक और एक कृषि क्षेत्र है जो हमें नकद समृद्ध करता है। कुल संचलन के मूल्य को बनाए रखा जा रहा है और बहुत समस्या नहीं होगी। अर्थशास्त्री और लेखक शेर सिंह ने कहा है कि संभव है कि सरकार बहुत से नकदी या कालेधन वाले लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है इसके अलावा सरकार ज्यादा से ज्यादा डिजीटल ट्रांजैक्शन चाहती है। 2000 के नोटों से जमाखोरी भी आसान होती है। केन्द्रीय बैंक के आर.टी.आई में दिए जवाब के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 3542.991 मिलियन के नोट छापे गए थे। हालांकि वर्ष 2017-18 में छपाई में काफी कमी आई और मात्र 111.507 मिलियन के नोट ही छापे गए जो 2018-19 में और कम होकर 46.690 मिलियन के नोट रह गए। वैसे भी सरकार इस तरह के इशारे तो करती ही रहती है कि 2000 के नोटों पर से धीरे-धीरे लोगों की निर्भरता को कम करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ सूत्रों से भी यह बात सामने आई थी कि आर.बी.आई. ने 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। यहां तक कि नवम्बर 2018 में एक आर.टी.आई. से भी ये पता चला था कि नासिक करंसी नोट प्रैस को 2000 के नोट छापने के आदेश नहीं मिले हैं। हालांकि यह भी कहा गया था कि सरकार का इसे वापस लेने का भी कोई प्लान नहीं है।

एसबीआई ने आपके बचत खाते पर चलाई कैंची, करोड़ों ग्राहकों को दिया बड़ा झटका

नई दिल्ली । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को देखते हुए बैंक डिपोजिट और फिक्स्ड डिपोजिट पर ब्याज कम कर दिया है। अब 1 लाख रुपये तक के बैंक डिपोजिट पर 3.50 फीसदी की जगह 3.25 फीसदी का ब्याज मिलेगा। ये नई ब्याज दरें 1 नवंबर 2019 से लागू होंगी। एसबीआई बैंक ने बैंक डिपोजिट के अलावा टर्म डिपोजिट और बल्क डिपोजिट पर भी ब्याज दरें क्रमशः10 बेसिस प्वाइंट और 30 बेसिस प्वाइंट घटा दी हैं। ये नई दर एक से दो साल तक के टर्म डिपोजिट पर लागू होंगी। ये नई दरें 10 अक्टूबर से लागू होंगी। एफडी पर ब्याज दरें घटाने के अलावा एसबीआई ने छठी बार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एमसीएलआर घटा दिया है। यानी, अब एसबीआई बैंक का होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि लोन लेना और सस्ता हो जाएगा। अब नई दरों के मुताबिक एमसीएलआर दर 10 अक्टूबर से 8.05 फीसदी होगी। एसबीआई ने ब्याज दरों में 10 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। दिवाली से पहले ब्याज दरों में कटौती कर एसबीआई बैंक ने लाखों ग्राहकों को तोहफा दिया है। एसबीआई बैंक की लोन पर नई ब्याज दरें 8.15 फीसदी से घटकर 8.05 फीसदी हो गई है। ये नई दरें 10 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। एसबीआई बैंक ने ब्याज दरें आरबीआई के रेपो रेट घटाने के बाद किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को दिवाली पर एक और तोहफा दिया था। आबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की जिसके बाद रेपो रेट 5.40 फीसदी से घटकर 5.15 फीसदी हो गई है।

गेल के विभाजन पर विचार करेगा मंत्रिमंडल, 2022 से पहले नहीं बेचा जाएगा पाइपलाइन कारोबार

नई दिल्ली(एजेंसी)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के पाइपलाइन कारोबार को अलग करके एक पृथक इकाई बनाने के प्रस्ताव पर अगले महीने तक विचार कर सकता है। हालांकि, रणनीतिक निवेशक को इसकी बिक्री 2022 से पहले नहीं की जाएगी। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। गेल देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस विपणन कंपनी है। देश के 16,234 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का दो-तिहाई से अधिक का स्वामित्व उसके पास है। प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सूत्रों ने बताया कि एक ही कंपनी के पास दोनों कारोबार होने की वजह से पैदा हो रही इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए गेल के विभाजन पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि गेल के पाइपलाइन कारोबार को अलग करके नई इकाई बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव पर इस महीने या नवंबर तक विचार कर सकता है या मंजूरी दे सकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद, पाइपलाइन कारोबार को एक अलग अनुषंगी इकाई में स्थानांतरित करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 8-10 महीने का समय लगेगा।

हालांकि, पाइपलाइन कारोबार वाली अनुषंगी कंपनी को रणनीतिक निवेशक को 2022 से पहले नहीं बेचा जा सकता है क्योंकि सरकार का मानना है कि गैस बाजार इससे पहले परिपक्व नहीं होगा और गेल को राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण करने के लिए सरकार के समर्थन की जरूरत होगी।

फैशन डिजाईनर के बंगले में चोरो का धावा

१ लाख कैश,तीन आईफोन समेत ३,७३ लाख की चोरी कर फरार

सूरत

शहर के सिटीलाइट विस्तार में रहनेवाली एक महिला फैशन डिजाइनर के बंगले को रात्रि दरमियान अनजान चोरो ने निशाना बनाया. अंदर घुसे चोर १ लाख की कैश और तीन आईफोन तथा अन्य सामान समेत ३,७३ लाख का माल चुराकर भाग गए.

मिली जानकारी के मुताबिक़ सिटीलाइट स्थित संगम सोसाइटी बंगला नंबर-२१ निवासी हिना प्राग मोदी फैशन डिजाइनर है. गत रात्रि दरमियान अज्ञात चोरो ने उनके बंगले को निशाना बनाया. बंगले में घुसे चोर नगद १ लाख रूपये, तीन आईफोन,दो लेपटॉप और एक आईपेड सहित ३,७३ लाख का माल चुराकर भाग निकले.सिटीलाइट विस्तार में रहनेवाली एक महिला फैशन डिजाइनर के बंगले को रात्रि दरमियान अनजान चोरो ने निशाना बनाया. अंदर घुसे चोर १ लाख की कैश और तीन आईफोन तथा अन्य सामान समेत ३,७३ लाख का माल चुराकर भाग गए.

लाखो रुपयों की चोरी की घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया.घटना की जानकारी दिए जाने पर उमरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर अनजान चोरो के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है.

विद्यार्थियों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अभिभावक समेत स्कूल पर भी होगी कार्रवाई

सूरत । पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही का फैसला किया है। राज्यभर में बगैर लाइसंस या हेल्मेट बगैर टू व्हीलर चलाने वाले विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावक और स्कूलों को खामियाजा भुगतना होगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस स्कूलों में खास अभियान चलाएगी और यदि स्कूल के बाहर वाहन मिलते हैं तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बगैर वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को जेल भी जाना पड़ सकता है। सूरत पुलिस फिलहाल में शहर में हेल्मेट और लाइसंस बगैर वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को बार बार समझाए जाने के बावजूद विद्यार्थी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिसे देखते हुए सूरत पुलिस ने अब विद्यार्थियों के साथ अभिभावक और स्कूल के खिलाफ कार्यवाही का फैसला कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब स्कूल के बाहर वाहन मिले तो उसे टो कर लिया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी, स्कूल और अभिभावकों की होगी। ऐसी समस्या के समाधान के लिए दो दिन ट्रैफिक पुलिस स्कूल और अभिभावकों के साथ बैठ करेगी। नए कानून की जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों देने के बावजूद यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो बुधवार से ट्रैफिक पुलिस तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए बार बार समझाए जाने के बावजूद इसका उल्लंघन किया जा रहा है।

यात्रियों की सुविधा के लिए

सोनगढ़ स्टेशन पर भी होगा बांद्रा टर्मिनस-पालिताना के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का ठहराव

सूरत .

यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन सं. 09027/09028 बांद्रा टर्मिनस-पालिताना सुपरफास्ट विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ को सोनगढ़ स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का निर्णय लिया गया है।

जानकारी केमुताबिक ट्रेन संख्या. 09027 बांद्रा टर्मिनस-पालिताना सुपरफास्ट विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से दोपहर ३.२५ बजे प्रस्थान कर अगले दिन 05.30 बजे पालिताना पहुँचेगी। यह ट्रेन 16 अक्टूबर, 2019 से 1 जनवरी, 2020 तक चलेगी।

इसी प्रकार, वापसी में ट्रेन संख्या. 09028 पालिताना-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ गुरुवार को पालिताना से 07.40 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 21.50 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 17 अक्टूबर, 2019 से 2 जनवरी, 2020 तक चलेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे। यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, वीरमगाम, बोटाद, ढोला जं., सोनगढ़ एवं सिहोर (गुजरात) स्टेशनों पर रुकेगी. पश्चिम रेलवे द्वारा अतिरक्त ठहराव के लिए किये गये निर्णय से यात्रियों को राहत मिलेंगी.

फायर विभाग की गिरी गाज

सिल्कसिटी मार्केट की ६०० दुकाने की गई सील

सूरत

सिल्कसिटी मार्केट में सोमवार के दिन भीषण आग लग गई थी.घटन की वजह से पुरे मार्केट में धुवा फ़ैल गया था और काफी अफरातफरी मच गई थी. काफी मशक्क के बाद आग की घटना पर काबू पाया गया था लेकिन इस घटना के बाद मार्केट में फायर सेफ्टी नहीं होने का खुलासा होने पर फायर विभाग ने ६०० दुकाने सील कर दी है.

जानकारी के मुताबिक़ फायर विभाग द्वारा सीलिंग की कार्यवाही करते हुए सिल्कसिटी मार्केट में ६०० दुकाने सील कर दी गई है,फायर के सख्त रुख को देखकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. उपरोक्त सभी दुकानों में फायर सेफ्टी नहीं होने के चलते सीलिंग की कार्यवाही की गई थी. सोमवार के दिन मार्केट मे आग लगने से पुरे मार्केट में धुवा फ़ैल गया था,घटना के बारे में जानकारी दिए जाने पर फायर विभाग का काफिला घटना स्थल पर पंहुचा था. घटना इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसे काबू करने में फायर कामरियो को काफी मशक्कत करनी पड़ी और ४ घंटे के बाद आग बुझाकर घटना पर काबू पाया गया. इस घटना के बाद ही यहाँ पर फायर सेफ्टी नहीं होने का खुलासा हुआ था.

परीक्षा रद्द हो जाने के मुद्दे पर विधार्थीओ का विरोध प्रदर्शन

कलक्टर को आवदेन पत्र देकर रद्द के निर्णय को वापस लेने की मांग की

सूरत.

बिन सचिवालय क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा अचानक रद्द हो जाने से लाखो विधार्थी के सपनो पर पानी फिर गया है.परीक्षा रद्द करने के सरकार के इस निर्णय का विधार्थीओ ने विरोध करते हुए कलकटर को आवेदन पत्र देकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई है.

जानकारी के मुताबिक़ आगामी २० अक्टूबर को बिन सचिवालय क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस पीरक्षा में गुजरात से १० लाख विधार्थी उमीदवार थे. लाखो विधार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए गणेश पर्व,नवरात्रि पर्व जैसी त्यौहार तक छोड़ दिए थे और महीनो से परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे. लेकिन सरकार द्वारा अचानक इस परीक्षा को रद्द करने देने का निर्णय लेने से लाखो विधार्थी चौक गए है.परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे विधार्थीओ को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देने लगे जिससे उनके समर्थन में आकर आम आदमी पार्टी द्वारा कलक्टर को आवेदन पत्र दिया गया और परीक्षा रद्द के नीर्णय को वापस लेने की मांग की गई है.

स्वास्थय मंत्री ने न्यू सिविल अस्पताल के अधिकारियो के साथ की बैठक

स्टेमसेल बिल्डिंग में तीन विभाग शिफ्ट करने के दिए निर्देश

सूरत.

स्वास्थय मंत्री नितिन पटेल सोमवार को शहर के दौरे पर थे. इसके बाद वह शाम को उन्होंने नई सिविल अस्पताल में विधायक,सांसद और अस्पताल के अधिकारियो के साथ बैठक की थी, बैठक में उन्होंने अधूरे रह गए स्टेमसेल बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर चर्चा की और उसी बिल्डिंग को उपयोग में लेने के हेतु से पुराने अस्पताल में स्थित मेडिसिन,गायनेक और पीडियाट्रिक विभाग को स्टेमसेल बिल्डिंग में शिफ्ट करने के निर्देश दिए.

नई सिविल अस्पताल परिसर में स्थित स्टेमसेल रिसर्च सेंटर अब अधूरा रह गया है. सिर्फ बिल्डिंग बनी रह गई है. सोमवार को स्वास्थय मंत्री नितिन पटेल ने मेडिकल कॉलेज में न्यू सिविल अस्पताल सुपरिंटेंडेंट,कॉलेज के डीन,अहमदाबाद से आये किडनी,हार्ट,और कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर तथा शहर के सांसद और विधायकों के साथ बैठक की थी. बैठक में नितिन पटेल ने दस मंजिला स्टेमसेल बिल्डिंग में गायनेक,मेडिसिन और पीडियाट्रिक विभाग को शिफ्ट करने के लिए मंजूरी दी है. इसलिए आगामी दिनों में यह तीनो विभाग स्टेमसेल प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जायेंगे. इसके बाद नितिन पटेल ने अधिकारियो के साथ स्टेमसेल बिल्डिंग,लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया.आगामी दिनों में नई बिल्डिंग में उपरोक्त तीनो विभागों के अलावा एक एक कर अन्य विभाग भी शिफ्ट किये जाएंगे.

बहन को मार देने की धमकी देकर विवाहिता से किया दुष्कर्म

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूरत.

अडाजण क्षेत्र में आरोपी एक विवाहिता को जबरन कमरे में खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने बहन को जान से मार देने की धमकी देकर विवाहिता को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

मिली जानकारी के मुताबिक़ अडाजण विस्तार में स्थित एसएमसी आवास निवासी आरोपी मुकेश जादव और घर के पास ही रहनेवाली आरती (नाम बदला है) के बिच प्रेम सबंध थे.रविवार शाम को दोनों पाल स्थित गौरवपथ रोड पर मिले थे वहा से आरोपी आरती को अपने के मित्र के घर पर लेकर गया था,और वहा उसके साथ शारीरिक रूप से छेड़खनी करने लगा था जिसका आरती विरोध करने लगी थी तब आरोपी ने उसे दो -तीन तमाचे मार दिए थे जिससे आरती ने अपनी बहन विवाहित बहन अनिता (नाम बदला है) को फोन करके कहा कि मुकेश उसे मार रहा है तू यहाँ पर आ जा. जिससे अनिता बहन को बचाने के लिए वहा पर पहुंची तब आरोपी मुकेश ने आरती को जान से मार देने की धमकी देकर अनिता को ही जबरन खींचकर कमरे में लेकर गया और उसके साथ जबरजस्ती कर दुष्कर्म किया.इस मामले में अनिता ने आरोपी मुकेश के खिलाफ अडाजण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई.पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है.

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)